



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2010/फाल्गुन 18, 1931

No. 65]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2010/PHALGUNA 18, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मार्च, 2010

सं. टीएएमपी/38/2007-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए पोत घाट सं. 10 पर प्रहस्तित कार्गो पर अंतिम (फाइनल) पोत घाट शुल्क तय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/38/2007-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास

.....आवेदक

आदेश

(फरवरी 2010 के 23वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/31/2004-एनएमपीटी दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के माध्यम से पोत घाट सं. 10 हेतु 1996-97 से 1999-2000 तक के लिए पोत घाट शुल्क की दर निर्धारित की थी।

2. अनेक अनुस्मारकों और अनुवर्तनों के बाद न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) ने दिनांक 16 जुलाई, 2007 के अपने पत्र द्वारा, वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए अंतिम (फाइनल) पोतघाट शुल्क प्रभार निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव दाखिल किया था। पत्तन द्वारा प्रस्तावित पोतघाट शुल्क दर वर्ष 2000-2001 के लिए रु. 73.32 प्रति टन और वर्ष 2001-2002 के लिए रु. 87.24 प्रति टन है। पत्तन ने बताया है कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ने एस्क्रो एकाउंट में पर्याप्त अधिशेष नहीं बनाए रखने और पत्तन की साझा परिसम्पत्तियों पर मूल्यों को न घटाने से संबंधित दो बिन्दुओं पर अपनी प्रेक्षाओं के अधीन प्रस्तावित पोतघाट शुल्क प्रभार से संबंधित गणनाओं की पुष्टि की है।

3. संबद्ध उपयोगकर्ता मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के साथ निर्धारित सामान्य परामर्शी प्रक्रिया पूरी की गई थी और एमआरपीएल की टिप्पणियों पर पत्तन की प्रतिपूरक सूचना प्राप्त की गई थी।

4. प्रस्तावित पोतघाट शुल्क दर की गणना के संबंध में एमआरपीएल द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं :-

(i) एमआरपीएल का तर्क था कि 1996-97 से पहले के वर्षों से संशोधित पेंशन-अशंदान के भाग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पोतघाट में प्रचलन वर्ष 1996 में ही आरम्भ हुआ था ।

(ii) एमआरपीएल एस्क्रो एकाउंट से धन निकासी के पत्तन के तरीके से भी सहमत नहीं हैं। इसने तर्क दिया है कि पत्तन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) जैसाकि पत्तन द्वारा वास्तव में वसूल किया गया है, की मद में प्रोद्धवनों (एक्युअल्स) की और साझा परिसंपत्तियों पर मूल्यों को जिसे ऋण वापसी के समक्ष सैट-ऑफ नहीं किया गया है और इसके साथ ही विशिष्ट वर्षों तक पत्तन द्वारा संचयी रूप से उगाहे गए अधिक पोतघाट शुल्क की मद में उभरने वाली धनवापसियों को यथावत रखे। इसने सत्यापन के बारे में, पत्तन से विस्तृत गणनाओं का अनुरोध किया है ।

5. एनएमपीटी ने बताया है कि पोतघाट शुल्क की गणना में अपनाई गई पेंशन देनदारी की जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकन मूल्यांकन के संदर्भ में पुनर्जार्च की गई है और पोतघाट को प्रभार्य समानुपातिक राशि, प्रस्ताव में विचारित रु. 5.84 करोड़ की तुलना में रु. 3.40 करोड़ ही आती है। एस्क्रो एकाउंट से निकासी के बारे में उठाए गए बिंदु के बारे में पत्तन ने व्यौरे प्रस्तुत किए हैं और निवेदन किया है कि एमआरपीएल ने रु. 843.63 लाख का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया था जिसको भी समायोजित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त फेर बदल के कारण पत्तन ने इन आंकड़ों को वर्तमान प्रस्ताव में या परवर्ती वर्षों के प्रस्तावों में समायोजित करने की आवश्यकता व्यक्त की है ।

6.1 इस प्रकरण में 17 दिसम्बर, 2009 को पत्तन परिसर में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, एमआरपीएल ने अपनी आपत्तियों पर पुनः जोर दिया। एनएमपीटी ने निवेदन किया है कि उसने एमआरपीएल की कुछ मांगों की जगह देने के लिए प्रस्ताव को संशोधित किया है। एमआरपीएल ने संशोधित प्रस्ताव में आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए और अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 30 दिन की मोहलत दी है जिसे इस प्राधिकरण ने प्रदान कर दिया। एनएमपीटी इस बात से सहमत था कि पुराने प्रस्ताव के आधार पर आरम्भ की गई प्रक्रिया को जारी रखने से कोई लाभ नहीं है और इसलिए इस प्रकरण को बंद करने पर वह सहमत हो गया ।

6.2 यद्यपि पत्तन ने संशोधित प्रस्ताव दाखिल करना स्वीकार कर लिया था, उसने केवल 8 दिसम्बर, 2009 को अपनी टिप्पणियां ही प्रस्तुत कीं जिनसे एमआरपीएल को भी अवगत करवाया गया था। इसलिए कहा जाता है कि पत्तन द्वारा दाखिल किया गया कोई भी संशोधित प्रस्ताव इस प्राधिकरण के पास लंबित नहीं है ।

7.1 उपरोक्त की दृष्टि से, यह प्राधिकरण इस प्रकरण को वापिस लिए गए के रूप में बंद करने का निर्णय लेता है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए पत्तन द्वारा दाखिल किया जाने वाला संशोधित प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है। एनएमपीटी को सलाह दी जाती है कि वह राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर, एमआरपीएल की टिप्पणियों के साथ संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दे। एनएमपीटी से जब संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा, उसे नया ही माना जाएगा ।

7.2 हमारे द्वारा बार-बार अनुरोध करने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पत्तन ने परवर्ती वर्षों के लिए अर्थात् 2002-2003 और उसके बाद के लिए पोतघाट शुल्क सं. 10 के लिए पोतघाट शुल्क दर तय करने की स्थिति में नहीं है। एनएमपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर, वर्ष 2002-2003 और इसके बाद समझौता ज्ञापन के स्थान ग्रहण करने तक पोतघाट शुल्क दर निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दे। इस प्राधिकरण को प्रस्तावित पोतघाट शुल्क दर और गणनाएँ भेजने से पहले, एनएमपीटी को, अभी तक पालन की गई सामान्य परंपरा के अनुसार एमआरपीएल से अपने आंकड़ों का सत्यापन करवाने की सलाह दी जाती है ।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th March, 2010

No. TAMP/38/2007-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the New Mangalore Port Trust for fixation of final wharfage on cargo handled at Jetty No. 10 for the years from 2000-01 and 2001-02 as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/38/2007-NMPT

New Mangalore Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 23rd day of February, 2010)

This Authority had vide Order No. TAMP/31/2004-NMPT dated 18th November, 2004 fixed the wharfage rate for Jetty No. 10 for the years 1996-97 to 1999-2000.

2. After several reminders and follow up, the New Mangalore Port Trust has filed the proposal for fixation of the final wharfage charges for Jetty No. 10 for the years 2000-01 and 2001-02 *vide* its letter dated 16th July, 2007. The wharfage rate proposed by the port is Rs. 73.32 per tonne for the year 2000-01 and Rs. 87.24 per tonne for the year 2001-02. The port has stated that the MRPL has confirmed the calculations relating to the proposed wharfage charges subject to its observation on two points relating to non-maintenance of sufficient balance in escrow account and non-reduction of depreciation on the common assets of the port.

3. The usual consultation procedure prescribed with the concerned user Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) was completed and the feedback of the port on the comments of the MRPL was obtained.

4. The main objections made by the MRPL regarding the calculations of the proposed wharfage rate are summarised below:

- (i) The MRPL argued that the portion of the pension contribution which pertained to years prior to 1996-97 should not be considered since the jetty commenced operations in the year 1996.
- (ii) The MRPL does not agree with the port's method of withdrawal of the amount from the Escrow Account. It has argued that the port is supposed to maintain accruals on account of Return on Investment (ROI) as charged actually by the port plus depreciation on common assets which is not setoff against loan repayment besides refunds arising on account of excess wharfage collected by port cumulatively upto the respective years. It has requested for detailed workings from the port in this regard for verification.

5. The NMPT has stated that the pension liability adopted in the calculation of wharfage has been re-examined with reference to the actuarial valuation done by the Life Insurance Corporation and the proportionate amount chargeable to Jetty comes to Rs. 3.40 crores as against Rs. 5.84 crores considered in the proposal. With regard to the point made about withdrawal from the Escrow account, the port has furnished details and submitted that the MRPL had derived extra benefit of Rs. 843.63 lakhs which also needs to be adjusted. Due to above modification, the port has expressed the necessity to adjust these figures in the current proposal or in the proposal for the subsequent years.

6.1. A joint hearing in this case was held on 17th December, 2009 at the port premises. At the joint hearing, the MRPL has reiterated its objection. The NMPT has submitted that it had revised its proposal to accommodate some of the demands of the MRPL. The MRPL has requested for atleast 30 days to verify the figures in the revised proposal and furnish its response which was agreed upon by this Authority. The NMPT agreed that no useful purpose will be served by continuing with the proceedings initiated based on its old proposal and therefore has agreed to close this case.

6.2. Though the port has claimed about filing a revised proposal, it has furnished only its comments on 8th December, 2009, which were shared with the MRPL. Therefore, no revised proposal stated to have been filed by the port is pending with this Authority.

7.1. In view of the above, this Authority decides to close this case as withdrawn. The revised proposal to be filed by the port for the years 2000-01 and 2001-02 is still awaited. The NMPT is advised to file its revised proposal along with comments of MRPL within one month from the date of notification of this Order in the Gazette. The revised proposal when received from NMPT will be treated afresh.

7.2. Despite repeated request by us and the Order of the Hon'ble High Court, the port has not filed any proposal for fixation of wharfage rate for Jetty No. 10 for the subsequent years i.e. from 2002-03 onwards and hence this Authority is not in a position to fix the wharfage rate for these years. The NMPT is directed to file the proposal for fixation of wharfage rate from the years 2002-03 onwards till the subsidence of the MOU within one month from the date of notification of this Order in the Gazette. Before forwarding the calculations and proposed wharfage rate to this Authority, the NMPT is advised to have the figures verified by the MRPL, as per the usual practice followed so far.

RANI JADHAV, Chairperson
[ADVT III/4/143/09-Exty.]